भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 814

दिनांक 07.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत के राजनयिक और आर्थिक संबंध

814. श्री जिया उर रहमान:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा पड़ोसी देशों के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंधों में सुधार लाने के प्रयास किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके प्रमुख परिणाम क्या हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) भारत सरकार अपने पड़ोसी देशों के साथ मजबूत और सहयोगात्मक संबंधों को बढ़ावा देने के महत्व को समझती है। 'पड़ोस प्रथम' नीति, जो भारत के अपने निकटतम पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के प्रबंधन का मार्गदर्शन करती है, स्थिरता और समृद्धि के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी, जन-उन्मुख, क्षेत्रीय ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें भौतिक, डिजिटल और लोगों से लोगों के बीच संपर्क का निर्माण भी शामिल है। भारत इन देशों के साथ परामर्शात्मक, गैर-पारस्परिक और परिणामोन्मुख आधार पर कार्य करता है, जो सम्मान, संवाद, शांति और समृद्धि के सिद्धांतों से प्रेरित है। भारत की 'पड़ोस प्रथम' नीति के एक भाग के रूप में, सरकार पड़ोसी देशों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार आवश्यक विकासात्मक सहायता और क्षमता निर्माण पहल कर रही है, जिससे उनके देशों के समग्र आर्थिक विकास में योगदान मिल रहा है। इस दृष्टिकोण के तहत, भारत बड़े पैमाने पर अवसंरचना से लेकर समुदाय से संबंधित परिसंपत्तियों और मंचों के प्रावधान, क्षमताओं के संवर्धन और वित्तीय, बजटीय और मानवीय सहायता प्रदान करने तक की अवसंरचना परियोजनाओं के विकास में पड़ोसी देशों की सहायता कर रहा है।

(ख) इस नीति के दायरे में भारत द्वारा अनेक पहल और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। प्रमुख हालिया गतिविधियों एवं पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) खाद्य और चिकित्सा सहायता के रूप में अफगानिस्तान को मानवीय सहायता, साथ ही अफगान छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं। पिछले कुछ वर्षों में, देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भारत ने अफगान लोगों को मानवीय सहायता की कई खेपों के साथ सहायता की है, जिसमें 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, 40,000 लीटर मैलाथियान (कीटनाशक), 300 टन चिकित्सा सहायता और 28 टन भूकंप राहत सहायता शामिल है। ये खेप संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (यूएनडब्ल्यूएफपी), इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान (आईजीआईसीएच), अफगान रेड क्रिसेंट सोसाइटी (एआरसीएस), आदि को सौंप दी गई है। भारत ने अफगानिस्तान में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) के साथ भी साझेदारी की है ताकि अफगान ड्रग उपयोगकर्ता आबादी, विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण के लिए सहायता प्रदान की जा सके।

दिनांक 8 जनवरी 2025 को विदेश सचिव दुर्बई में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। हमने विकास सहायता के कुछ पहलुओं में सहयोग की संभावना भी तलाशी है।

(ii) **बांग्लादेश** में अगस्त 2024 में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद, भारत सरकार ने द्विपक्षीय बातचीत जारी रखी है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य सलाहकार प्रो. मुहम्मद यूनुस ने 16 अगस्त 2024 को टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधान मंत्री मोदी के निमंत्रण पर, मुख्य सलाहकार प्रो. मुहम्मद यूनुस ने 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में भाग लिया। विदेश मंत्री ने 24 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क में 79^{वाँ} संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार श्री तौहीद हुसैन से मुलाकात की। विदेश सचिव ने 9 दिसंबर 2024 को ढाका का दौरा किया और मुख्य सलाहकार प्रो. मुहम्मद यूनुस और विदेश मामलों के सलाहकार हुसैन से मुलाकात की।

भारत ने बांग्लादेश में सीमा पार बिजली, ऊर्जा और परिवहन संपर्क के क्षेत्रों में कई विकास सहयोग परियोजनाओं का समर्थन किया है। भारत बांग्लादेश को विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता प्रदान कर रहा है, जिसमें अखौरा-अगरतला रेल लिंक का निर्माण और बांग्लादेश में अंतर्देशीय जलमार्गों की ड्रेजिंग शामिल है। 26 अक्टूबर को, पश्चिम बंगाल के पेट्रापोल में एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) पर एक नए अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल भवन और "मैत्री द्वार" नामक दूसरे द्वार का उद्घाटन किया गया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पार व्यापार और आवागमन अवसंरचना को बढ़ाना है। अक्टूबर 2024 में, भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने भारतीय पावर ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश तक 40 मेगावाट बिजली के संचरण के लिए एक त्रिपक्षीय बिजली बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किए।

(iii) **भूटान** के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पिछले एक साल में कई उच्च स्तरीय आदान-प्रदान हुए हैं। हाल ही में, भूटान के महामहिम राजा ने 5-6 दिसंबर 2024 को भारत का दौरा किया, जिसके दौरान महामहिम ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। महामहिम ने प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर महाकुंभ मेले में भाग लेने के लिए 03-04 फरवरी 2025 को फिर से भारत का दौरा किया।

जहां तक हमारी विकास साझेदारी का संबंध है, भारत ने भूटान की 13^{वीं} पंचवर्षीय योजना के लिए अपना समर्थन दोगुना करके 10,000 करोड़ रुपये कर दिया है, जिसमें भूटान की आर्थिक सुधार के लिए भूटान की शाही सरकार के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के लिए समर्थन भी शामिल है। वर्तमान में, भारत भूटान में दो जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है- पुनात्सांगछू-I (1200 मेगावाट) और पुनात्सांगछू-II (1020 मेगावाट)। पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना की पहली दो इकाइयां दिसंबर 2024 में चालू हो गई थीं। सरकार ने हाल ही में तीसरे देश के नागरिकों के भूमि मार्ग से प्रवेश और निकास को सुविधाजनक बनाने के लिए दर्रागा (असम)/समद्रुप जोंगखर (भूटान) में एक आत्रजन चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है। आज तक, भूटान की 13^{वीं} योजना के तहत भारत सरकार की सहायता से परियोजना संबद्ध सहायता के तहत 61 परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है। दिसंबर 2024 में, भारत सरकार ने भूटान के राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए ग्यालसुंग अकादमियों के निर्माण हेतु भूटान को रियायती ऋण की अंतिम किश्त (कुल 1,500 करोड़ रुपये) जारी की।

(iv) **मालदीव** के साथ विकास सहयोग भारत-मालदीव द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिलाओं में से एक है। भारत सरकार मालदीव में प्रमुख ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (जीएमसीपी) को लागू कर रही है, जो ग्रेटर माले क्षेत्र के चार द्वीपों को जोड़ेगा। इसके अलावा, भारत सरकार की सहायता से की जा रही अन्य प्रमुख विकास परियोजनाओं में मालदीव में गण और हनीमाधू हवाई अड्डों का पुनर्विकास, मछली प्रसंस्करण इकाइयां, अड्डू शहर पुनर्विकास परियोजना, जल और स्वच्छता परियोजनाएं, 4,000 सामाजिक आवास इकाइयों का निर्माण और उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएं (एचआईसीडीपी) शामिल हैं। मालदीव के राष्ट्रपति 6-10 अक्टूबर 2024 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान, दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से 700 सामाजिक आवास इकाइयों और हनीमाधू हवाई अड्डे के रनवे का उद्घाटन किया और उन्हें सौंप दिया इससे पहले, विदेश मंत्री ने अगस्त 2024 में मालदीव की आधिकारिक यात्रा की, जिसके दौरान दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से 34 द्वीपों में से 28 में जल और स्वच्छता परियोजनाओं, अड्डू पुनर्ग्रहण परियोजना और अड्डू चक्कर लिंक रोड सहित 6 भारत-सहायता प्राप्त उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (एचआईसीडीपी) का उद्घाटन और हस्तांतरण किया। नवंबर 2024 में, भारत और मालदीव ने दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच सीमा पार लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा, भारत और मालदीव मालदीव में यूपीआई भुगतान अवसंरचना के संचालन पर मिलकर काम कर रहे हैं। जनवरी 2025 में, मालदीव के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने भारत सरकार

द्वारा अनुदान सहायता के माध्यम से मालदीव में चरण- III के तहत एचआईसीडीपी को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

(v) मानवीय राहत के अतिरिक्त, कई कनेक्टिविटी अवसंरचना विकास परियोजनाओं और क्षमता निर्माण के लिए **म्यांमार** को सहायता प्रदान की गई है। मौजूदा सुरक्षा स्थिति से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, चल रही सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाओं और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (केएमटीटीपी) और भारत-म्यांमार-थाईलैंड (आईएमटी) त्रिपक्षीय राजमार्ग सहित प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए लगातार प्रयास किए गए। भारत सड़कों, स्कूलों और छोटे स्वास्थ्य केंद्रों सहित नागरिक अवसंरचना के निर्माण के लिए उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (एचआईसीडीपी) और त्वरित प्रभाव परियोजनाओं (क्यूआईपी) के तहत पूरे म्यांमार में जन-केंद्रित विकास परियोजनाओं को लागू कर रहा है।

(vi) **नेपाल** के साथ, भारत के पास विकास सहयोग का एक बहुत व्यापक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और आर्थिक, ऊर्जा, डिजिटल और सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करना है, जिसमें अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पेयजल सुविधाएं, स्वच्छता, जल निकासी, ग्रामीण विद्युतीकरण, जल विद्युत, तटबंध और नदी प्रशिक्षण कार्यों के निर्माण में उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (एचआईसीडीपी) के कार्यान्वयन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। अक्टूबर 2024 में, भारत ने नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित परिवारों का समर्थन करने के लिए आवश्यक स्वच्छता आपूर्ति, दवाएं, जीवन रक्षक जैकेट, सोने की चटाई, खाद्य पदार्थ, रबरयुक्त इन्फ्लैटेबल नौकाएं, मोटर, तिरपाल, स्लीपिंग बैग, कंबल, क्लोरीन की गोलियां और बोटलबंद पानी सहित 25 टन से अधिक मानवीय सहायता प्रदान की। एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में 15 नवंबर 2024 को भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश तक पहले त्रिपक्षीय बिजली लेनदेन का उद्घाटन किया गया। सितंबर 2024 में, अनुसमर्थन विलेख को सौंपे जाने के बाद नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बन गया।

(vii) **श्रीलंका** के साथ विकास साझेदारी में कनेक्टिविटी, कृषि, बिजली, शिक्षा, मानव संसाधन विकास, संस्कृति और आर्थिक जुड़ाव के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता कार्यक्रम भी शामिल है। श्रीलंका के मौजूदा राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने 15-17 दिसंबर 2024 तक भारत की राजकीय यात्रा की। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान, भारत और श्रीलंका ने 'साझा भविष्य के लिए साझेदारी को बढ़ावा देने' के लिए संयुक्त वक्तव्य को अपनाया। राजकीय यात्रा के एक भाग के रूप में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित घोषणाएं की गईं:

1) जाफना विश्वविद्यालय और पूर्वी विश्वविद्यालय से लाभार्थियों के शैक्षणिक पाठ्यक्रम के समापन तक प्रतिवर्ष 100 नए छात्रों को वित्तीय सहायता योजना।

2) माहो-अनुराधापुरा खंड में सिग्नलिंग परियोजना के लिए 14.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता प्रदान करना।

इसके अतिरिक्त, यात्रा के दौरान निम्नलिखित समझौतों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए:

1) दोहरे कराधान से बचने और आय पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच समझौते को संशोधित करने वाला प्रोटोकॉल।

2) श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी), भारत सरकार और श्रीलंका विकास प्रशासन संस्थान (एसएलआईडीए) के बीच समझौता ज्ञापन। दिनांक 4 अक्टूबर 2024 को, विदेश मंत्री इस वर्ष देश की अपनी दूसरी यात्रा के दौरान नव शपथ ग्रहण करने वाले राष्ट्रपति दिसानायके द्वारा प्राप्त होने वाले पहले विदेशी गणमान्य व्यक्ति बन गए। श्रीलंका के साथ भारत के विकास सहयोग के हिस्से के रूप में, जून 2024 में, श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और विदेश मंत्री ने संयुक्त रूप से कोलंबो और त्रिकोमाली जिलों में मॉडल विलेज हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत 48 घर और कैंडी, मटाले और नुवारा एलिया जिलों में भारतीय आवास परियोजना के चरण III के तहत 106 घर सौंपे। अक्टूबर 2024 में कोलंबो की यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री ने पूरी हो चुकी एलओसी परियोजनाओं से संबंधित भुगतानों को कवर करने के लिए 20.66 मिलियन अमरीकी डॉलर की अनुदान सहायता के विस्तार और कांकेसंधुराई बंदरगाह को आधुनिक बनाने के लिए 61.5 मिलियन अमरीकी डॉलर की अनुदान सहायता की घोषणा की। उन्होंने श्रीलंकाई रेलवे को 22 डीजल इंजन उपहार में देने की भी घोषणा की।